प्रेषक,

करूणेश कुमार सिंह,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1-दुग्ध आयुक्त, दुग्धशाला विकास, उ0प्र0, लखनऊ।
2-दुग्धशाला विकास अधिकारी/उप दुग्धशाला विकास अधिकारी/आहरण वितरण अधिकारी, दुग्धशाला विकास विभाग, उ0प्र0, आगरा, मैनपुरी, झांसी, जालौन, हमीरपुर, महोबा, बांदा, लखनऊ, लखीमपुर-खीरी, बरेली, शाहजहांपुर, पीलीभीत, मेरठ, रामपुर, वाराणसी, मिर्जापुर, सोनभद्र, गोरखपुर, महराजगंज, देवरिया, बस्ती, सिद्धार्थनगर, आजमगढ़, मऊ, प्रयागराज, प्रतापगढ़, कानपुर, अयोध्या, अम्बेडकरनगर, गोण्डा एवं बहराइच।

दुग्ध विकास अनुभाग-2 लखनऊ : दिनांक 24 मार्च, 2023

विषयः- वित्तीय वर्ष 2022-23 में दुग्ध उत्पादकों को तकनीकी निवेश योजनान्तर्गत अनुदान (अनुदान संख्या-16 जिला योजना-सामान्य) के अन्तर्गत तृतीय किश्त की वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक दुग्ध आयुक्त, दुग्धशाला विकास, उ0प्र0 के पत्रांक-592/दुग्ध-4/नियो0/तकनीकी निवेश-सामान्य(277)/21-22, दिनांक 10 मार्च, 2023 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2022-23 में दुग्ध उत्पादकों को तकनीकी निवेश (जिला योजना, अनुदान संख्या-16) के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि रू0 464.10 लाख के सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में शासनादेश संख्या-20/2022/548/001-53-2002-50-2019, दिनांक 13 जुलाई, 2022 द्वारा रू0 77.35 लाख एवं द्वितीय किश्त के रूप शासनादेश संख्या-7/2023/1102/002-53-2002-50-2019, दिनांक 07 फरवरी, 2023 द्वारा रू0 77.35 लाख की वित्तीय स्वीकृति निर्गत की गयी। सन्दर्भगत मद में अवशेष धनराशि रू0 309.40 लाख में से तृतीय किश्त के रूप रू0 77.35130 लाख (रूपये सतहत्तर लाख पैंतीस हजार एक सौ तीस मात्र) प्रदेश के 75 जनपदों के लिए 50 प्रतिशत धनराशि दुधारू पशुओं हेतु दवा (डिवर्मर, थनैला व टिक कन्ट्रोल) तथा 50 प्रतिशत धनराशि दुग्ध उत्पादन में वृद्धि के लिए पशु आहार व मिनरल मिक्चर हेतु वित्तीय स्वीकृति संलग्न विवरण के अनुसार सम्बन्धित दुग्धशाला विकास अधिकारी/उप दुग्धशाला विकास अधिकारी/आहरण वितरण अधिकारी के निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

नियम व शर्ते/प्रतिबन्ध

(1) धनराशि के आहरण एवं व्यय के दौरान योजना विषयक गाईडलाइन्स का पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा ।

(2) प्रश्नगत धनराशि का व्यय उन्हीं कार्य एवं मदों हेतु किया जायेगा, जिस हेतु धनराशि का बजट प्राविधान किया गया है, इसकी पूर्ण जिम्मेदारी दुग्ध आयुक्त, दुग्धशाला विकास, उ0प्र0 की होगी।

(3) प्रश्नगत धनराशि का व्यय बजट प्राविधान से इतर कार्य/मदों में किया जाना वित्तीय अनियमितता होगी ।

(4) स्वीकृत की जा रही धनराशि को आहरित कर बैंक/डाकघर में नहीं रखा जायेगा ।

(5) स्वीकृत की जा रही धनराशि को निर्धारित मद में व्यय कराने व उपयोगिता प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराये जाने का दायित्व दुग्ध आयुक्त, दुग्धशाला विकास, उ0प्र0 का होगा।

(6) दुग्ध आयुक्त, दुग्धशाला विकास, उ0प्र0 यह सुनिश्चित करेंगे कि स्वीकृत किये जा रहे कार्य/मद हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा अन्य किसी स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है और न ही यह कार्य किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में सम्मिलित है।

(7) उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव में आंकडों की शुद्धता का दायित्व दुग्ध आयुक्त, दुग्धशाला विकास, उ0प्र0 का होगा ।

(8) वित्तीय स्वीकृतियॉ जारी करने अथवा धनराशि को विभागाध्यक्ष/नियंत्रक अधिकारी के निवर्तन पर रखे जाने से पूर्व दुग्ध आयुक्त, दुग्धशाला विकास, उ0प्र0 के स्तर पर की जाने वाली समस्त औपचारिकताओं की पूर्ति अनिवार्यतः सुनिश्चित कर ली जाये। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का विभागाध्यक्ष/नियंत्रक अधिकारी के निवर्तन पर रखे जाने मात्र से किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नही देता है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2-इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(9) व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययता के संबंध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(10) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष में ही सुनिश्चित किया जायेगा।

(11) स्वीकृत की जा रही धनराशि के सम्बन्ध में वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-13/2022/बी-1-454/ दस-2022-231/ 2022, दिनांक- 07 जून, 2022 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा एवं समय-समय पर निर्गत संगत शासनादेशों में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(12) पूर्व में अवशेष धनराशि के उपभोग करने के उपरान्त ही स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण आवश्यकतानुसार किया जायेगा।

(13) प्रश्नगत वित्तीय स्वीकृति उपलब्ध बजट प्राविधान की सीमा के अन्तर्गत रहने का उत्तरदायित्व दुग्ध आयुक्त, दुग्धशाला विकास, उ0प्र0 का होगा ।

(14) विभागाध्यक्षों/ अन्य नियंत्रक अधिकारियों द्वारा बजट आवंटन में इस बात का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाये कि आहरण एवं वितरण अधिकारियों द्वारा कोषागार से धनराशि का आहरण तत्काल आवश्यकता होने पर ही किया जाये।

(15) कोषागार से एकमुश्त धनराशि का आहरण न किया जाये, क्योकि धनराशि के एकमुश्त आहरण से राज्य के कैश मैनेजमेंट पर प्रतिकूल प्रभाव पडता है।

(16) उक्त स्वीकृत की जा रही धनराशि में से अनुरक्षण मद में कोई धनराशि व्यय नहीं की जायेगी। यदि किसी अनुरक्षण मद पर कोई व्यय आवश्यक हो, तो संबंधित दुग्ध संघ/समितियां अपने संसाधन से वहन करेगें।

(17) स्वीकृत की जा रही धनराशि जिला योजना हेतु आवंटित परिव्यय में समायोजित होगी। अवमुक्त धनराशि से किसी भी दशा में अधिक व्यय न किया जाये तथा समस्त व्यय सम्बन्धित शासनादेशों/नियमों में उल्लिखित शर्तों व प्रतिबन्धों के अधीन किया जायेगा। व्यय में किसी भी प्रकार की अनियमितता के लिए सम्बन्धित आहरण वितरण अधिकारी/ धनराशि का उपयोग करने वाले इकाई प्रभारी व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे। किसी भी प्रकार के विचलन की स्थिति में वे स्वयं ही उत्तरदायी होगें।

(18) उक्त धनराशि का आहरण करने तथा सम्बन्धित दुग्ध संघों को उपलब्ध कराने के बाद स्वीकृत धनराशि का निर्धारित प्रयोजन पर उपयोग सुनिश्चित कराकर उपयोगिता प्रमाण-पत्र दुग्ध आयुक्त को यथासमय उपलब्ध कराने का दायित्व सम्बन्धित प्रबन्धक/सामान्य प्रबन्धक, दुग्ध संघ एवं उप दुग्धशाला अधिकारी का होगा।

(19) स्वीकृत धनराशि का आहरण तथा उसके उपयोग के सम्बन्ध में आहरण अधिकारी के लेखे बही खाते एवं सम्बन्धित दुग्ध संघों के लेखे एवं बही खाते भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक तथा उनके द्वारा प्राधिकृत अधिकारियों के अवलोकनार्थ /परीक्षणार्थ उपलब्ध रहेंगे।

(20) जिन मदों में व्यय के पूर्व वित्तीय हस्त-पुस्तिका के अधीन शासन/सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति/सहमति आवश्यक है, उनमें धनराशि व्यय करने के पूर्व अनिवार्य रूप से शासन/सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति/अनुमोदन प्राप्त कर लिया जाये ।

(21) दुग्ध आयुक्त, दुग्धशाला विकास विभाग द्वारा संबंधित दुग्ध संघों को प्रश्नगत कार्यक्रम में उपलब्ध कराई जा रही धनराशि का निर्धारित मदों में उपयोग सुनिश्चित कराते हुए उसका उपयोगिता प्रमाण-पत्र संकलित कर शासन को आगामी किश्त की आवश्यकता से पूर्व उपलब्ध कराया जायेगा ।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 77,35,130 (रुपये सतहत्तर लाख पैंतीस हजार एक सौ तीस मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या 016 लेखा शीर्षक 2404001020301 दुग्ध उत्पादकों को तकनीकी निवेश (जिला योजना) मानक मद 20 सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन) के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न संख्या E-1- 558 -X-2022-23, दिनांक- 22 मार्च, 2023 मे प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

<u>संलग्नक -यथोक्त।</u>

भवदीय,
करूणेश कुमार सिंह
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2-इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

संख्या-15 /2023/230(1) /002-53-2002-50-2019, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज ।

2- महालेखाकार,(लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, लखनऊ/प्रयागराज ।

3- वरिष्ठ आडिट आफिसर (आडिट प्लानिंग) कार्यालय महालेखाकार, लेखा परीक्षा (प्रथम), सत्यनिष्ठा भवन, 15 थार्नहिल रोड, प्रयागराज ।

4- सम्बन्धित मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।

5- सम्बन्धित जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

6- प्रबन्धक निदेशक, पी0सी0डी0एफ0लि0, 29-पार्क रोड, लखनऊ।

7- सम्बन्धित मुख्य विकास अधिकारी, उ0प्र0।

8- सम्बन्धित वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी उ0प्र0।

9- वित्त नियन्त्रक, दुग्धशाला विकास, उ0प्र0 लखनऊ।

10- वित्त(व्यय-नियन्त्रण) अनुभाग-1/नियोजन अनुभाग-3/राज्य योजना आयोग-3, उत्तर प्रदेश शासन ।

11- सम्बन्धित मण्डलीय उप निदेशक, अर्थ एवं संख्या प्रभाग, उत्तर प्रदेश।

12- सम्बन्धित अर्थ एवं संख्याधिकारी उ0प्र0।

13- वेब मास्टर, दुग्धशाला विकास विभाग, जवाहर भवन, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि इसे विभागीय वेबसाइट पर प्रदर्शित करें।

14- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
पंकज कुमार सिंह,
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2-इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।